

मोदी की टैरिफ नीति के आगे झुका अमेरिका

रिश्ते सुधारने को ट्रंप अब भारत के साथ बनाना चाहते हैं नया 'C-5 सुपरक्लब'

राष्ट्रबाण

वाशिंगटन. भारत पर हैवी टैरिफ लगाने वाला अमेरिका पीएम मोदी की कूटनीति के आगे आखिरकार नवमस्तक होता दिख रहा है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब हाई टैरिफ की वजह से भारत के साथ बिगड़े रिश्ते को बैलेंस करने के लिए 5 महाशक्तिशाली देशों का नया C-5 सुपरक्लब बनाना चाहते हैं. ट्रंप इस सुपरक्लब में भारत को प्रमुख शक्ति के रूप में शामिल करना चाहते हैं. यह दावा अमेरिकी प्रकाशन पॉलिटिको की रिपोर्ट में किया गया है. इस सुपर क्लब में भारत-अमेरिका के अलावा रूस, चीन और जापान को शामिल करने की बात कही गई है.

क्या है ट्रंप का मकसद

रिपोर्ट के अनुसार नई संस्था का मकसद एक ऐसा प्रमुख शक्तियों का समूह बनाना है जो G7 की उन शर्तों से बंधा न हो कि सदस्य देश अभीर भी हों और लोकतांत्रिक भी. इस रणनीति में प्रस्तावित 'कोर फाइव' (C5) में संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, भारत और जापान शामिल हैं. यानी वे देश जिनकी आबादी 10 करोड़ से ज्यादा है.



चीन और रूस के साथ भी पावर बैलेंस करना चाहता है अमेरिका

ट्रंप के इस प्लान से साफ है कि वह भारत को साधने के साथ ही साथ चीन और रूस के साथ भी अपने रिश्तों को सुधारना चाहता है. ताकि पूर्वी एशिया में अमेरिका अपनी खोई हुई इमेज को फिर से सुधार सके और भारत, रूस व चीन जैसे देशों के साथ दुश्मनी के आयाम को कम कर सके.

पॉलिटिको की रिपोर्ट में और क्या है?

पॉलिटिको की रिपोर्ट के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप कथित तौर पर एक नया एलीट 'C5' यानी 'कोर फाइव' वैश्विक शक्ति समूह बनाने पर विचार कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, भारत और जापान शामिल होंगे. यह मौजूदा यूरोप-प्रधान G7 और अन्य लोकतंत्र-आधारित धनी देशों के समूहों को दरकिनार कर देगा. हालांकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन अमेरिकी प्रकाशन पॉलिटिको ने रिपोर्ट किया कि इस नए 'हार्ड-पावर' समूह का विचार पिछले हफ्ते काइस्ट हाउस द्वारा जारी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के लंबे अप्रकाशित संस्करण में सामने आया था.

नये C5 में यूरोप की कोई जगह नहीं

उन्होंने नोट किया कि इस सैद्धांतिक C5 में यूरोप की कोई जगह नहीं है, "जिससे यूरोपीय लोगों को लगता कि यह प्रशासन रूस को यूरोप में अपना प्रभाव क्षेत्र रखने वाली प्रमुख शक्ति मानता है.

C5 का पहला प्रस्तावित एजेंडा

C5 का पहला प्रस्तावित एजेंडा मध्य पूर्व में सुरक्षा, खासकर इजरायल और सऊदी अरब के बीच संबंधों का सामाजीकरण करना है. रिपोर्ट के अनुसार काइस्ट हाउस ने इस दस्तावेज के अस्तित्व से इनकार किया है. प्रेस सेक्रेटरी हन्नाह केली ने जोर दिया कि 33 पेज की आधिकारिक योजना का कोई 'वैकल्पिक, निजी या गुप्त संस्करण' नहीं है.

फास्ट ट्रैक

बालाघाट में शिवलिंग का अपमान

राष्ट्रबाण
बालाघाट. मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में एक शिवलिंग के ऊपर जलपात्र में मटन ग्रेवी डालने से भक्तों में आक्रोश पनप गया और उन्होंने नाराजगी जताई है. धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाले इस मामले में यह बात सामने आई कि जलपात्र से ग्रेवी नीचे शिवलिंग पर गिर रही थी. जानकारी में आया कि जल चढ़ाने की मटकौ में भी मटन का मिश्रण अर्थात ग्रेवी रखी मिली है जो कि प्लास्टिक बोतल में लाकर उसमें डाली गई है. वहीं पुलिस ने आरोपी युवक योगेश नागवंशी निवासी स्नेह नगर बालाघाट को गिरफ्तार कर लिया है.दरअसल, घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के गर्ग शंकरघाट की है. रोज की तरह स्थानीय निवासी गजानंद पटले अन्य साथी के साथ पहुंचे और पूजा कर रहे थे.

देहरादून से दुबई तक पहुँचने वाला 22 करोड़ का नेटवर्क

राष्ट्रबाण
कानपुर. कानपुर पुलिस के हथ्थे चढ़ चुके महाठग रविंद्र नाथ सोनी की कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म

की स्क्रिप्ट से कम नहीं. गिरफ्तारी के बाद एसआईटी के सामने वह खुद को बेचारा, कंगाल और कचौड़ी का ठेला चलाकर परिवार पालने वाला आदमी बताता रहा.

देहरादून वाले प्लैट से शुरू हुई परतें खुलने की कहानी

कानपुर में गिरफ्तारी के बाद एसआईटी ने उसे रिमांड पर लिया और सबसे पहले देहरादून पहुंची, जहां उसका आलीशान प्लैट था . इस घर में उसकी पत्नी और बेटी रहती थीं. पुलिस को वहां जो उम्मीद थी, वह नहीं मिला क्योंकि सोनी पहले ही जरूरी दस्तावेज गांवब कर चुका था. लेकिन पूरे प्लैट की जांच करते-करते पुलिस को उसकी आर्थिक पहुंच की झलक मिल गई. एक-एक करके टीम को पता चला कि दिल्ली के करोड़पति बाम में उसकी दुकानें, एनसीआर में लग्जरी प्लैट, दुबई में करोड़ों की कीमत के दो अपार्टमेंट और दुबई के दो बैंक खातों में भारतीय मुद्रा के अनुसार करोड़ों रुपये जमा हैं.

आस्था

तय हुई शिलान्यास की तारीख

पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के बाद राम मंदिर भी बनेगा

राष्ट्रबाण
कोलकाता. मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होने के बाद कोलकाता में राम मंदिर बनाने का फैसला किया गया है. संजय पायरा को इस काम के लिए कन्वीनर की जिम्मेदारी दी गई है. हालांकि, इस मंदिर को बनाने वाले लोगों का राजनीति से कोई संबंध नहीं होगा. वहीं, हुमायूं कबीर ने पहले ही अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने और असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन करने का ऐलान कर दिया है.



बाबरी मस्जिद का शिलान्यास 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में हुआ था. विधायक हुमायूं कबीर विवादों के

राम नवमी पर होगा शिलान्यास

बिधानमगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन परिया स्मेत कई जगहों पर बैनर लगाए गए हैं. मंदिर बनाने के कन्वीनर संजय पायरा का दावा है कि 26 मार्च को राम नवमी के दिन मंदिर का शिलान्यास होगा और काम शुरू हो जाएगा. लेकिन सिर्फ मंदिर ही नहीं. उन्होंने दावा किया है कि राम मंदिर के साथ स्कूल, हॉस्पिटल और ओल्ड एज होम भी बनाए जायेंगे.

बावजूद पाँछे नहीं हटे और मस्जिद की नींव रखी. इसके बाद कोलकाता में राम मंदिर निर्माण के पोस्टर लगा दिए गए हैं. साल्टलेक करुणामयी, सिटी सेंटर, समेत कई जगहों पर राम मंदिर बनाने के बैनर लगाए गए.

हर जंग के बाद एक तानाशाह

क्या आसिम मुनीर को झेलने के लिए तैयार है पाकिस्तान!

राष्ट्रबाण
नई दिल्ली. पाकिस्तान की राजनीतिक-सैन्य इतिहास की किताबें खोलें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है. यहाँ भारत के खिलाफ हर बड़ी जंग या सैन्य अभियान के बाद देश में एक तानाशाह उभरता है. 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद जनरल जिया-उल-हक ने सत्ता हथिया ली, कारगिल युद्ध के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने तख्तापलट कर दिया, और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद आसिम मुनीर तानाशाह बनने की राह पर चल चुका है. आसिम मुनीर का पहले तो फोल्ड मार्शल बनना और फिर संविधान संशोधन द्वारा चीफ ऑफ



डिफेंस फोर्सेज (CDF) बनना इसी की ओर इशारा है. पाकिस्तान की आजादी के 78 सालों में से 33 साल सैन्य तानाशाहों के शासन में गुजरे हैं. पहला बड़ा उदाहरण 1958 में जनरल अयूब खान का तख्तापलट था, इसी बीच 1965 की भारत-पाकिस्तान की लड़ाई में अयूब पर दबाव बढ़ा, लेकिन चूंकि वह खुद ही मिलिट्री तानाशाह थे इसलिए वे प्रेशर झेल गए.

1971 की लड़ाई, अशांति और तख्तापलट

लेकिन 1971 का युद्ध एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ . इस युद्ध में पाकिस्तान की हार और बांग्लादेश का जन्म हुआ, पाकिस्तान को ये हार जनरल याह्या खान के नेतृत्व में ही झेलनी पड़ी थी. उनकी पाकिस्तान में खूब बेइज्जती हुई . देश में तख्तापलट की अप्वाहल चल रही थी . ऐसा लग रहा था सैन्य अधिकारियों का एक ग्यूप कभी भी तख्तापलट कर सकता है. 1971 में पाकिस्तान की हार 16 दिसंबर को हुई थी. याह्या खान ने आगे की अशांति को रोकने के लिए 20 दिसंबर 1971 को राष्ट्रपति पद और सरकार की बागडोर को उस समय की शक्तिशाली और लोकप्रिय पीपुल्स पार्टी के महात्माकाशी नेता जुल्फिकार अली भुट्टो को सौंप दी.

भारत तैयार खरीद बढ़ाने को, लेकिन US एग्री पर सख्त रोक

राष्ट्रबाण
नई दिल्ली. भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बड़ा अपडेट सामने आया है. सरकारी सूत्रों के मुताबिक, भारत ने अमेरिका से कई सेक्टर्स पर डील करने के लिए सहमति जाहिर की है, लेकिन अभी एग्रीकल्चर सेक्टर पर सहमति नहीं बन पाई है. सरकारी सोर्स के अनुसार, भारत ने ट्रेड डील के तहत US से पर्नार्नी प्रोडक्ट खरीदने का वादा किया है. इसके अलावा, डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने और एंविपेशन इक्विपमेंट खरीदने पर भी सहमति जाहिर की है. वहीं भारत का टारगेट है कि यूएस डील से पहले 25 फीसदी

रेसिप्रोकल टैरिफ भी कम कराने का लक्ष्य

अमेरिका ने भारत पर अभी 50 फीसदी का टैरिफ लगाया है . 25 फीसदी रेसिप्रोकल टैरिफ और 25 फीसदी एक्स्ट्रा टैरिफ. ऐसे में सरकारी सूत्रों का कहना है कि भारत यूएस से डील से पहले 25 फीसदी एक्स्ट्रा टैरिफ तो हटाने को कहेगा ही . साथ ही रेसिप्रोकल टैरिफ 25 फीसदी को भी कम करने को कह सकता है .

एग्रीकल्चर पर राजी नहीं भारत

Informist न्यूज एजेंसी के मुताबिक, सरकारी सूत्रों ने कहा कि अमेरिका से व्यापार वार्ता के दौरान भारत ने एग्रीकल्चर सेक्टर को साइड में रख दिया है और उसपर नेगोशिएशन नहीं करना चाहता है . सीधे शब्दों में कहें तो भारत ने अमेरिका कृषि उत्पादों को भारतीय बाजारों में एंटी देने से मना कर दिया है . भारत का मानना है कि अमेरिकी कृषि उत्पादों को अनुमति देने से धरलू किसानों पर प्रतिस्पर्धा का दबाव बढ़ सकता है और उनकी कमाई कम हो सकती है . इस कारण इस ट्रेड डील में एग्रीकल्चर को शामिल नहीं किया गया है .

एक्स्ट्रा टैरिफ को हटया जाए, इस डील के तहत दोनों देशों का लक्ष्य व्यापारिक संबंधों को संतुलित करना और टैरिफ विवादों को हल करना

है. भारत चाहता है कि डील से पहले अमेरिका एक्स्ट्रा 25 फीसदी टैरिफ को हटा दे, ताकि भारत वस्तुओं की अमेरिकी बाजार में

पहुंच फिर बढ़ सके. इसके बाद ट्रेड डील के अगले स्टेप में भारत बाकी 25 फीसदी टैरिफ में भी कटौती की मांग रख सकता है.



पर कहा था कि, “अगर अस्पृश्यता पाप नहीं है तो दुनिया में कुछ भी पाप नहीं है.” ऐसा नहीं है कि उनसे पहले के सरसंघचालकों ने इस विषय पर कुछ कहा नहीं लेकिन जिस तरह से

“दलित नेताओं की नाराजगी बिल्कुल सही है”

देवरस के बयान के बाद संघ की प्रतिनिधि सभा में भी आरक्षण को लेकर प्रस्ताव आया. इस मौके पर बालासाहब ने कहा था, “दलित नेताओं की भाषा अक्षेपपूर्ण है, यह सही है, किंतु हम सभी लोग यदि दलित समाज के सदस्य होते, अनेक वर्षों तक सामाजिक अत्याचार, विभक्ता, अन्याय, असहनीय वेदना, दुख, आप्मान आदि सहना पड़ता तो हम किस भाषा में बोलते, इस पर विचार कर प्रस्ताव का निर्णय करें” और प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ . उनका अपना घर नागपुर में पिछड़े दलित परिवारों से घिरा हुआ था .

दलितों के विषयों को प्रमुखता से बालासाहब ने रखा और देश भर में जो संदेश गया, वैसा जरूर पहले नहीं हुआ था. शाखा में उन सबको जोड़ना, उनको घर पर लाकर साथ

भोजन करना, उस दौर में आसान नहीं था. बाद में सामाजिक समरसता दिवस और सेवा भारती जैसे संगठन के जरिए उन्होंने दलितों के उद्धार के लिए जो काम किए,

आय से अधिक संपत्ति मामले में EOU की कार्रवाई

बैंक अधिकारी के 6 ठिकानों पर छापेमारी



शुरू की गई. कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के

आरोपों के आधार पर की जा रही है. EOU के शुरुआती आकलन के

आय से अधिक संपत्ति मामले में 6 जगहों पर छापेमारी

EOU की टीम ने पटना सहित कई जिलों में स्थित उनके आवास, दफ्तर और अन्य संपत्तियों पर छापेमारी की है. कार्रवाई के दौरान टीम बैंक खाते, संपत्ति के कागजात, निवेश सहित कई दस्तावेजों की जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि छापेमारी में निकलने वाले सबूत भवेश कुमार के खिलाफ केस को और मजबूत करेंगे. सूत्रों के मुताबिक, EOU को लंबे समय से भवेश कुमार की संपत्ति में असामान्य वृद्धि की जानकारी मिल रही थी. जांच अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी के दौरान अलग-अलग एगल से उनकी संपत्ति की जांच की जा रही है जिसमें जमीन, मकान, निवेश और चल-अचल संपत्ति शामिल है.

अनुसार भवेश कुमार सिंह ने वैध आय के मुकाबले करीब 60

फीसदी अधिक अवैध संपत्ति इकट्ठा की है.

पहले 'काफिर' घोषित किए गए भुट्टो

फिर जिया ने किया तख्तापलट

राष्ट्रबाण

नई दिल्ली. पाकिस्तान की राजनीतिक-सैन्य इतिहास की किताबें खोलें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है. यहाँ भारत के खिलाफ हर बड़ी जंग या सैन्य अभियान के बाद देश में एक तानाशाह उभरता है. 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद जनरल जिया-उल-हक ने सत्ता हथिया ली, कारगिल युद्ध के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने तख्तापलट कर दिया, और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद आसिम मुनीर तानाशाह बनने की राह पर चल चुका है. आसिम मुनीर का पहले तो फोल्ड मार्शल बनना और फिर संविधान संशोधन द्वारा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज (CDF) बनना इसी की ओर इशारा है. पाकिस्तान की आजादी के 78 सालों में से 33 साल सैन्य तानाशाहों



के शासन में गुजरे हैं. पहला बड़ा उदाहरण 1958 में जनरल अयूब खान का तख्तापलट था, इसी बीच 1965 का तख्तापलट था, इसी बीच 1965 की भारत-पाकिस्तान की लड़ाई में अयूब पर दबाव बढ़ा, लेकिन चूंकि वह खुद ही मिलिट्री तानाशाह थे इसलिए वे प्रेशर झेल गए. भुट्टो को काफिर घोषित किया गया बावत यहां तक बिगड़ गई थी कि कुछ दलों ने भुट्टो को काफिर घोषित कर दिया.1977 के चुनावी धांधली विरोधी आंदोलन के दौरान भुट्टो को स्पष्ट रूप से “काफिर” घोषित किया गया था, और यह घोषणा विपक्षी गठबंधन जुल्फिकार अली भुट्टो को पाकिस्तान नेशनल अलायंस (PNA) “काफिर” करार दिया था.

1971 की लड़ाई, अशांति और तख्तापलट

लेकिन 1971 का युद्ध एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ . इस युद्ध में पाकिस्तान की हार और बांग्लादेश का जन्म हुआ, पाकिस्तान को ये हार जनरल याह्या खान के नेतृत्व में ही झेलनी पड़ी थी. उनकी पाकिस्तान में खूब बेइज्जती हुई . देश में तख्तापलट की अप्वाहल चल रही थी . ऐसा लग रहा था सैन्य अधिकारियों का एक ग्यूप कभी भी तख्तापलट कर सकता है. 1971 में पाकिस्तान की हार 16 दिसंबर को हुई थी. याह्या खान ने आगे की अशांति को रोकने के लिए 20 दिसंबर 1971 को राष्ट्रपति पद और सरकार की बागडोर को उस समय की शक्तिशाली और लोकप्रिय पीपुल्स पार्टी के महात्माकाशी नेता जुल्फिकार अली भुट्टो को सौंप दी.

वेनेजुएला और अमेरिका में चरम पर पहुंचा तनाव

मादुरो की मदद को आ गए पुतिन; ट्रंप के खेमे में खलबली

राष्ट्रबाण

मॉस्को. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा वेनेजुएला का तेल टैंकर युक्त जहाज जब्त किए जाने के बाद से दोनों देशों में तनाव चरम पर पहुंच गया है. अमेरिकी नौसेना ने 2 दिन पहले कैरेबियन सागर में वेनेजुएला की जहाज पर कमांडो कार्रवाई को अंजाम देकर अपने कब्जे में ले लिया था. ट्रंप ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया था. वहीं वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने इसे संप्रभुता का उल्लंघन और अमेरिका की डकैती करार दिया था. ऐसे में दोनों देशों के बीच तनाव पहले से



कई गुना बढ़ गया है. इस बीच मादुरो की मदद करने रूस के राष्ट्रपति पुतिन की एंटी हो चुकी है. पुतिन का यह कदम अमेरिका में खलबली की वजह बन सकता है. **अमेरिका ने मादुरो पर लगाया है**

पुतिन ने मादुरो से की बात

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो और ट्रम्प प्रशासन के बीच बढ़ते तनाव के बीच ‘वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता’ व्यक्त की. क्रैमलिन ने बयान में कहा कि पुतिन ने मादुरो के साथ फोन पर बात की और वेनेजुएला के नेता की नीति का समर्थन दोहराया जो “बढ़ते बाहरी दबाव के सामने राष्ट्रीय हितों और संप्रभुता की रक्षा” करती है. यह कॉल उस दिन के बाद आया जब अमेरिकी सेनाओं ने वेनेजुएला के तट से एक तेल टैंकर जब्त कर लिया, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन की मादुरो पर दबाव बढ़ाने की नवीनतम रणनीति है .

नार्को-आतंकवाद का आरोप: मादुरो पर अमेरिका में नार्को-आतंकवाद के आरोप लगे हैं. गुरुवार को कांग्रेस के समक्ष गवाही के दौरान होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने जहाज की जब्ती को क्षेत्र में

ट्रम्प प्रशासन के नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान से जोड़ा. अमेरिका ने दशकों में क्षेत्र में अपनी सबसे बड़ी सैन्य उपस्थिति बढ़ाई है और कथित ड्रग तस्करी वाली नावों पर घातक हमले किए हैं.

कौन हो सकता है यूपी बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष?

सामने आया यह नाम, केंद्रीय नेतृत्व की भी है पहली पसंद

राष्ट्रबाण

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में नए बीजेपी अध्यक्ष के नाम को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. सूत्रों के हवाले से महाराजगंज से भाजपा सांसद पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं. ओबीसी वर्ग में कुर्मी बिरादरी से पंकज चौधरी आते हैं. इस रैस में सबसे आगे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ही चल रहे हैं. पंकज चौधरी केंद्रीय नेतृत्व की भी पसंद बने हुए हैं. यूपी के नए

अमी भूपेंद्र सिंह चौधरी हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष

बता दें कि वर्तमान में यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी हैं. उनका कार्यकाल जनवरी 2025 में समाप्त हो चुका था, जिसके बाद से पद खाली पड़ा हुआ है. हालांकि, आधिकारिक रूप से उन्हें ही वर्तमान अध्यक्ष माना जा रहा है, जब तक यूपी बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिल जाता है.



बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर शनिवार को लखनऊ में नामांकन होगा. परसो इसकी घोषणा की जाएगी. हालांकि, औपचारिक ऐलान बाकी है. यूपी बीजेपी के अध्यक्ष

के लिए सबसे प्रबलत दावेदार में पंकज चौधरी का ही नाम चल रहा है. पंचायत और विधानसभा चुनाव के लिए है महत्वपूर्ण बीजेपी ने नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

अमृतसर के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी

चंडीगढ़. अमृतसर के कई प्राइवेट स्कूलों में शुक्रवार सुबह बम की धमकी वाले ईमेल मिलने से अफरा-तफरी मच गई. इससे स्टूडेंट्स, फेरेंट्स और स्टाफ में दहशत फैल गई. धमकी भरे ईमेल में दवा किया गया था कि उनके कैम्पस में बम रखा गए हैं. ये मैसेज कई जाने-माने स्कूल प्रिंसिपल और मैनेजमेंट टीम को मिले. सभी ने एक जैसे पैटर्न और शब्दों का इस्तेमाल किया गया था. इसकी सूचना स्कूलों ने तुरंत पुलिस को दी और इमरजेंसी सेफ्टी प्रोटोकॉल शुरू किए. **जिले के सभी स्कूल बंद करने के आदेश:** धमकी की सूचना मिलते ही डीसी अमृतसर ने जिले के सभी स्कूलों को तुरंत बंद करने के आदेश दिया हैं. बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने स्कूल बंद करने का फैसला लिया. डीसी अमृतसर ने स्कूलों को तुरंत खाली करने का भी आदेश दिया है. बाँद्री इलाकों में स्कूल खाली कराए जा रहे हैं. माता-पिता को मैसेज भेजे जा रहे हैं कि वे अपने बच्चों को जल्द से जल्द स्कूलों से निकाल लें.

बंगाल में चिंतित करने वाला घटनाक्रम

इस तस्वीर की हमने शायद ही कल्पना की हो कि देश में कहीं पर फिर से बाबरी मस्जिद की नींव डाली जाएगी और उसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल होंगे. तुपमूल कांग्रेस से निर्लंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद जिले में बेलंडगा इलाके में प्रतीकात्मक तौर पर फीता काटकर मस्जिद की नींव रख दी. हुमायूं कबीर पश्चिम मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर से विधायक हैं. वे लंबे समय से सार्वजनिक वक्तव्य दे रहे थे कि छह दिसंबर को बाबरी मस्जिद के निर्माण की शुरुआत करेंगे. इस कारण बंगाल के अंदर और देश में असहजता का माहौल कायम हो रहा था. अलग-अलग मंचों से इसे रोकने की मांग भी की गई, किंतु मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की. केवल हुमायूं कबीर को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निर्लंबित कर दिया. इसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता.



आखिर हुमायूं कबीर के साथ मुस्लिम समुदाय के इतने लोगों के खड़े होने, रुपये देने का विश्लेषण कोई कैसे करेगा? कुछ लोग इसे पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़ कर देख सकते हैं. अगर हुमायूं कबीर को बाबर के नाम पर वोट मिलने की उम्मीद है तो इससे खतरनाक स्थिति कुछ नहीं हो सकती. हुमायूं कबीर की सांप्रदायिक और हिंदू विरोधी मानसिकता लंबे समय से सामने है. मई 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि मुर्शिदाबाद में 70 प्रतिशत जनसंख्या मुस्लिम है. भाजपा के समर्थकों को भागीरथी नदी में फेंक देगे.

कानून-व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध कोई भी राज्य सांप्रदायिकता भड़काने और तनाव फैलाने की योजना वाले हुमायूं कबीर जैसे व्यक्ति को गिरफ्तार करता, हिरासत में लेता या कम से कम उसे नजरबंद करता. इसके साथ ऐसे कार्यक्रम पर रोक भी लगाता. मुर्शिदाबाद का दृश्य इसके विपरीत था. ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस उस कार्यक्रम की सुरक्षा के लिए वहां तैनात है. जब पुलिस-प्रशासन को राजनीतिक नेतृत्व से रोकने का कोई आदेश नहीं था तो वह ऐसी ही भूमिका निभाएगा.

किसी को भी कानूनी रूप से वैध जमीन पर मंदिर या मस्जिद बनाने का अधिकार है, लेकिन बाबर के नाम से मस्जिद बनाना करोड़ों हिंदुओं-सिखों की भावनाओं को चोट पहुंचाना और उनके जख्मों को कुदरेदान है. यह हर दृष्टि से अस्वीकार्य है. 1529 में बाबर के सेनापति मीर बक़ी द्वारा अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद निर्माण के विरुद्ध वर्षों का संघर्ष अब सबको पता है. अंततः स्वतंत्रता के बाद ऑलंदन और फिर आगे न्यायिक संघर्ष से उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद मंदिर निर्माण किया गया. बावजूद इसके देश का एक वर्ग मानता है कि बाबर के साथ उसका जुड़ाव है, उससे प्रेरणा मिलती है और इसलिए उसके नाम की मस्जिद बनानी है. यह भारत की एकता-अखंडता और सांप्रदायिक सहभाव की दृष्टि से अशुभ संकेत है. इससे बड़ी विवर्धना क्या होगी कि जिस बाबर को उसके मूल स्थान के कई इतिहासकार लुटेरा कहते हैं, अनेक भारतीय मुसलमान स्वयं को उससे जोड़ते हैं? हुमायूं कबीर के बाद तहरीक मुस्लिम शब्बन नामक संगठन ने ग्रेटर हैदराबाद में बाबरी मस्जिद मेमोरियल और वेलफेयर इंस्टीट्यूशन बनाने का आंदोलन किया है. पता नहीं आगे कौन कहां बाबर के नाम पर और कुछ निर्माण की घोषणा कर दे. भारत विभाजन के पीछे बंगाल वैचारिक एवं क्रियात्मक रूप से कट्टरपंथियों के लिए बहुत बड़ी ताकत बना था.



■ **मेष**: यह दिन आपके कॉन्फिडेंस में बूस्ट लेकर आएगा. आपके सारे काम तेजी से पूरे होने वाले हैं. कोई पुराना काम आज आपको खुशी दे सकता है क्योंकि इसमें अच्छी खासी ग़ोथ देखने को मिलेगी. परिवार में माहौल शांत रहेगा. बस खर्चा सोच समझकर करें. साथ ही जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें.

■ **वृषभ**: इस दिन आप थोड़े से इमोशनल हो सकते हैं. हालांकि आपका दिन अच्छा जाएगा. काम में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिलेगा. आज आपकी बात किसी खास शख्स के साथ हो सकती है. आज के दिन आपको पैसों के मामले में थोड़ी सावधानी रखनी है. देर रात खाना खाने से बचें.

■ **मिथुन**: यह दिन आपके लिए काफी लकी साबित होने वाला है. कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ने के संकेत है. आपको आज इससे जुड़ी कोई ना कोई खुशखबरी जरूर मिलेगी. दोस्तों के साथ आप अच्छा समय बिता पाएंगे. साथ ही परिवार के साथ भी खुशियों में शामिल होंगे.

■ **कर्क**: इस दिन आप एकदम शांत

आत्मनिर्भर बनने का सही रास्ता

बीते दिनों जब दक्षिण कोरिया के बुराना में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग से भेंट की थी तो उन्होंने इस भेंट को जी-2 का नाम दिया था. यानी उन्होंने एक तरह से मान लिया कि अमेरिका के बाद चीन दूसरी विश्व महाशक्ति बन चुका है, जिसे रोकना अब उसके वश की बात नहीं है और सोवियत संघ के विघटन के बाद एकध्रुवीय विश्व अब फिर से द्विध्रुवीय है. ऐसे पहले कार्यकाल में ट्रंप चीन को सबक सिखाने की बातें किया करते थे, पर अब उनके सुर पूरी तरह बदल चुके हैं.

वैसे ट्रंप इस वार्ता से पहले ही चीनी उत्पादों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की योजना को एक साल के लिए स्थगित कर चुके थे. फिलहाल चीनी उत्पादों पर अमेरिका 47 प्रतिशत का ही टैरिफ लगा रहा है. भारत जिसके साथ सामरिक साझेदारी को अमेरिकी नेता पिछले दो दशक से 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय साझेदारी बताते न थे, उसके उत्पादों पर 50 प्रतिशत का टैरिफ है, जबकि अमेरिका अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी देश चीन पर उससे कम टैरिफ लगा रहा है.

ट्रंप से जब ताइवान पर चीनी हमले के खतरे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह जह बज होगा, तब देखेंगे.



ट्रंप ने यह नहीं कहा कि वे ट्रेड डील का भय दिखाकर ताइवान को चीनी हमले से बचा लेंगे. इससे उलट ट्रंप हर तीन-चार दिन में भारत को लज्जित करने के लिए आपरेशन सिंदूर रकवाने का झूठा दावा यह कहकर करते हैं कि उन्होंने व्यापारिक समझौता न करने का भय दिखाकर संभावित परमाणु युद्ध रकवा दिया. रूस से कच्चा तेल भारत और चीन, दोनों ही आयात कर रहे हैं, पर ट्रंप प्रशासन हाथ धोकर भारत के ही पीछे पड़ा है. इस सबसे समझा जा सकता है कि चीन के सामने नतमस्तक अमेरिकी शासन तंत्र ने अब यह ठाना है कि अगर चीन विश्व की दूसरी महाशक्ति बन ही गया है और उसे रोकना उसके वश की बात नहीं रही है तो कम से कम भारत और रूस का उभार तो रोक ही जाए.

चीन की इस मजबूत स्थिति के पीछे उसकी सामरिक रूप से महत्वपूर्ण

तकनीक के अनुसंधान और उत्पादन में पहल करने की दशकों की नीति रही है. चीनी रणनीतिकारों ने ऐसे सेक्टरों और तकनीकी उत्पादों को चिह्नित किया, जिनके माध्यम से अमेरिका और विश्व को अपने ऊपर निर्भर बनाया जा सके. परिणाम-स्वरूप चीन आज ऐसे कई उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को नियंत्रित करता है और उनके माध्यम से उसने ट्रंप के टैरिफ युद्ध का मुहंतेज जवाब दिया है. ट्रंप ने चीन के उत्पादों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दी तो उसने अमेरिका को रेयर आर्ज अलॉयस यानों, रक्षा उपकरणों, इलेक्ट्रिक कारों से लेकर हेडफोन बनाने के लिए आवश्यक हैं और ये

नाचन बनाना चाहता था बोरीवली को ‘स्वतंत्र राष्ट्र’!

ठाणे जिले के शांत बोरीवली गांव में परसों आधी रात वह धमाका हुआ, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. घोर अंधेरे में दौड़ती काली गाड़ियां, बुलेटप्रूफ कमांडो, चारों दिशाओं से बढ़ती टीमें और पलक झपकते ही पूरा गांव घेराबंदी की जद में आ गया. यह कार्रवाई साकीब नाचन के कारण हुई. आतंक पैठैलाने के आरोप में गिरफ्तार नाचन की गत जून में मौत हो गई थी. पता चला है कि नाचन बोरीवली गांव को ‘स्वतंत्र राष्ट्र’ घोषित करने की गुप्त योजना बना रहा था. इस खुलासे ने सुरक्षा एजेंसियों को चौंका दिया था. खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के अनुसार, जांच में सामने आया कि साकीब खुद को किसी गुप्त शासन का मुखिया मानकर ‘अल-शाम स्टेट’ नाम के राष्ट्र की संरचना तैयार कर रहा था. वह अंदर ही अंदर युवाओं को कट्टर विचार, कोड भाषा और भूमिगत कामकाज की ट्रेनिंग दी जा रही थी. उसने फंडिंग के लिए डिजिटल, नकली और एन्क्रिप्टेड लेन-देन का जाल पैठैला रखा था, जिसकी भनक ईडी को लगी. दूसरी ओर एटीएस पहले ही साकीब की गतिविधियों पर नजर रखे बैठी थी.

महाराष्ट्र के गांवों पर कब्जा कर रहा गुजरात!



राजस्व कागजात और नागरिक अधिकारों से जुड़े कार्यों में भारी भ्रम पैदा हुआ है. इसी बीच दोनों राज्यों द्वारा शुरू की गई संयुक्त पैमाइश ग्रामीणों के घेराव के चलते रुक गई, जिससे वर्षों से लंबित यह विवाद फिर अनिश्चितता में फंस गया और शासन-व्यवस्था व सीमा सुरक्षा की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न खड़े हो गए हैं. महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्यों की सीमा रेखा पर पुराना विवाद एक बार फिर चर्चा में है. तलासरी तालुका के छह ग्राम पंचायतों की सीमा के मुद्दे के कारण तनाव पैदा हुआ है.



हाराष्ट्र और गुजरात सीमा पर तनाव फिर भड़क उठा है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि महाराष्ट्र की जमीन पर गुजरात की घुसपैठ और दखल-अंदाजी बढ़ रही है. गुजरात, तलासरी तालुका के वेवजी, गिरगाव, घोमाणीया, झाई, संभा और अच्छाड जैसे गांवों में सड़कें और पक्की इमारतें खड़ी कर रहा है. कहा गया है कि गृगल मैप पर गलत सीमा दिखना विवाद के लिए नया हथियार मिल गया है. इससे प्रशासनिक रिकॉर्ड, राजस्व कागजात और नागरिक अधिकारों से जुड़े कार्यों में भारी भ्रम पैदा हुआ है. इसी बीच दोनों राज्यों द्वारा शुरू की गई संयुक्त पैमाइश ग्रामीणों के घेराव के चलते रुक गई, जिससे वर्षों से लंबित यह विवाद फिर अनिश्चितता में फंस गया और शासन-व्यवस्था व सीमा सुरक्षा की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न खड़े हो गए हैं. महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्यों की सीमा रेखा पर पुराना विवाद एक बार फिर चर्चा में है. तलासरी तालुका के छह ग्राम पंचायतों की सीमा के मुद्दे के कारण तनाव पैदा हुआ है.

ट्रेड डील पर समानता आधारित समझौते की अपेक्षा

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के संबंध में कुछ सकारात्मक संकेत सामने आ रहे हैं. लेकिन इस बीच कुछ आशंकाएं भी जताई जा रही हैं कि क्या इस बातचीत में परस्पर समानता पर आधारित हित सुनिश्चित होने और एक संतुलित समझौते की राह साफ होगी. गौरतलब है कि प्रस्तावित व्यापार समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने की कोशिश के तहत अमेरिकी दल वार्ता के लिए भारत में है.

इसी बीच अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीयर ने कहा कि व्यापार समझौते के संदर्भ में भारत की ओर से ‘अब तक के सबसे अच्छे प्रस्ताव’ मिले हैं. माना जा रहा है कि इस बयान का उद्देश्य अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए शुल्क से उपजे गतिरोध को दूर करने की कोशिश करना है. इसकी वजह यह है कि एकतरफा और मनमानी शुल्क नीति के जरिए दबाव बनाने की कोशिश के समांतर व्यापार समझौते के लिए वार्ता में सकारात्मक नतीजों की उम्मीद नहीं की जा सकती. फिर व्यापार वार्ता में गतिरोध की एक मुख्य वजह ही अमेरिका की नई शुल्क नीति रही है. इसलिए यह देखने की बात होगी कि इस मसले पर अमेरिका के रुख में कितना बदलाव आ पाता है.



सकारात्मक दिशा में बढ़ने के मद्देनजर जारी कोशिशों के तहत ही भारत और अमेरिका के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते का सवाल अब एक मुख्य बिंदु है. इससे पहले अमेरिका का रवैया आमतौर पर यही सामने आ रहा था कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता हो, लेकिन

उसकी शर्तों पर. इसी क्रम में उसने शुल्क लगाने के फैसले को दबाव के एक औजार के रूप में इस्तेमाल किया. उसकी यह मंशा अधूरी रही, क्योंकि नुकसान की तमाम आशंकाओं के बावजूद भारत ने इस मसले पर अपना स्वतंत्र रुख बरकारार रखा. इसके बावजूद, यह हकीकत है कि

अमेरिका के शुल्क लगाने से उपजी परिस्थिति अंतरराष्ट्रीय व्यापार परिदृश्य पर विपरीत प्रभाव तो डाल ही रही थी. भारत के सामने भी कुछ चुनौतियां खड़ी होने की आशंका बनी रही. इसलिए भारत ने थोड़ा व्यावहारिक नीति पर आगे बढ़ते हुए अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने में रुचि दिखाई है, लेकिन इसके पीछे समानता आधारित समझौते का आसना भी है. अमेरिकी शुल्कों में कटौती, भारतीय उत्पादों के अमेरिकी बाजार में आसान प्रवेश, रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी, दवा और सेमी-कंडक्टर उद्योग आदि व्यापार वार्ता के मुख्य मुद्दों में शामिल हो सकते हैं. मुश्किल वहां आ सकती है, जिसमें अमेरिका भारत से कृषि, डेयरी और डिजिटल नीति के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण रियायतों पर जोर दे रहा है.

जाहिर है, भारत के लिए थोड़ा सजग रहने का वकत है, क्योंकि अमेरिका के साथ वार्ता में खासतौर पर कृषि क्षेत्र से जुड़े कई सवाल उभरे हैं. हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने यहां के किसानों की आमदनी कम होने के लिए कुछ अन्य देशों सहित भारत के चावल की बिक्री को जिम्मेदार ठहराया. दूसरी ओर, अगर अमेरिका अपना मक्का, गेहूं, कपास और सोयाबीन जैसे उत्पाद भारतीय बाजारों में निर्यात करता है, तो इससे भारत के छोटे किसानों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा पर विपरीत असर पड़ सकता है. इसी तरह, किसी समझौते की स्थिति में भारत को कृषि और जेनेटिकली माडिफाइड, यानी आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों पर भी छूट देने के मामले में सतर्क रहने की जरूरत है.

कर्नाटक में हेट स्पीच पर नया बिल

कर्नाटक विधानसभा में हेट स्पीच और हेट क्राइम के खिलाफ बिल पेश किया गया है. इसका मकसद है नफरत और घृणा फैलाने वाले अपराधों व बयानों को नियंत्रित करना. अक्सर कई ऐसे बयान आते रहते हैं, जिससे समाज में वैमनस्य बढ़ता है. इसे देखते हुए ऐसे कानून जरूरी लगते हैं, लेकिन इसके साथ चिंता भी है - दुरुपयोग की.



कहा था कि नागरिकों की जान की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है. उसी साल तहसील पुनावाला जमजंम आया, जिसमें राज्यों के लिए कई दिशा-निर्देश थे. आलोचना और नफरत . लेकिन, जब इतना कड़ा कानून आता है, तो उसके दुरुपयोग की आशंका भी बढ़ जाती है. भले ही बिल में अपराध की विस्तृत व्याख्या की गई हो, लेकिन असल चुनौती है इसे लागू करने में. कौन-सी बात नफरत फैलाने वाली है और कहां आलोचना की गई है - इसमें समझ की थोड़ा भी अंतर बढ़ा टकराव पैदा कर सकता है. इसी तरह, असहमति के अधिकार को भी सुरक्षित रखने की जरूरत है.

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता . बिल में सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी शामिल किया गया है. इंटरनेट पर जिस तेजी से दुष्प्रचार और वैमनस्य बढ़ाने वाले कंटेंट बढ़े हैं, उसे देखते हुए बिल उपयोगी हो सकता है, पर यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आड़े नहीं आना चाहिए. बिल को लेकर कई आशंकाएं और राजनीतिक विरोध है. कर्नाटक BJP का आरोप है कि यह बिल खास समूह को निशाना बनाने के लिए लाया जा रहा है. ऐसे में यह जरूरी है कि इस तरह का इंतजाम और निगरानी हो कि यह बिल किसी से बदला लेने का नहीं, बल्कि शांति कायम करने का टूल बने.

पाबंदी की राह, क्या वास्तव में सोशल मीडिया के संजाल से बच्चे बच सकेंगे?

इसमें कोई दोराय नहीं कि इंटरनेट की सुविधा ने दुनिया के दायरे को बहुत छोटा बना दिया है, लेकिन इसके समांतर एक सच यह भी है कि आभासी दुनिया में सोशल मीडिया के बहुतेरे मंचों पर सीमाओं से परे लोगों के बीच संवाद का विस्तार हुआ है, तो यथार्थ के धरातल पर लोग एक-दूसरे से दूर भी होते गए हैं. यह बहुत संभव है



कि आस-पड़ोस के बच्चे सोशल मीडिया के किसी मंच पर तो आपस में दोस्त हों, संवाद करते हों और साथ में कोई गेम खेलते हों, लेकिन वास्तव में वे कभी नहीं मिलते. यानी आभासी दुनिया में बच्चों का दायरा विस्तृत होता है, लेकिन यथार्थ के धरातल पर वे अकेले होते हैं. ऐसे में बिना आइट के एकाकीपन का दंश बच्चों के भीतर उतरता है, जो उन्हें आत्मघाती अवसाद के घेरे में ला दे सकता है. किसी एप के संजाल में फंसे बच्चों के मनोवैज्ञानिक परेशानियों का शिकार होने से लेकर आत्महत्या करने तक की खबरें आती रही हैं. दुनिया भर में सोशल मीडिया पर अति-सक्रियता के मानसिक और शारीरिक दुष्प्रभावों के मद्देनजर बच्चों के लिए इसके इस्तेमाल पर रोक लगाने या सीमित करने के सुझाव सामने आते रहे हैं. इस क्रम में आस्ट्रेलिया ने एक ठोस पहल करते हुए अपने यहां सोलह वर्ष से कम के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर बुधवार से पाबंदी लागू कर दी है. हालांकि संदेश भेजने और गेम खेलने वाले कुछ मंचों को इस प्रतिबंध से अलग रखा गया है. आस्ट्रेलिया में इस सख्त नियम के लागू होने के बाद बच्चों को उनका बचपन वापस मिलने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रतिबंध के लागू होने का स्वरूप क्या है और क्या वास्तव में सोशल मीडिया के संजाल से बच्चे बच सकेंगे.

कोशिश करें. ■ **कुंभ**: आपको अपने गुरू से पर थोड़ा कंट्रोल रखना है. किसी से बात करते वकत अपने शब्दों पर ध्यान रखें. ऑफिस मीटिंग में लोगों का सुझाव ध्यान से सुनें. पैसों के मामले में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है. सेहत से जुड़ी चीजों को नजरअंदाज ना करें. खानपान सही करें. ■ **मीन**: दिमाग शांत रहेगा तो आप सारी चीजें सही से कर पाएंगे. इसी के साथ आप फैसले भी सही लेंगे. अगर क्रश से दिल की बात कहनी है तो शुभ समय है. प्रोफेशनल लाइफ में ग़ोथ दिखेगी. छोटे-छोटे लाभ होने तय हैं. परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा. सेहत का थोड़ा ध्यान रखें. जरूरत लगे तो काम के बीच ब्रेक जरूर लें.

दोस्त आपकी मदद कर सकता है. लव लाइफ में सुधार आएगा. ■ **घनु**: यह दिन आपके लिए अच्छा जाने वाला है. आपके सारे मनचाहे काम पूरे होने की उम्मीद है. साथ ही कोई पुराना विवाद अब खत्म हो सकता है. इसके अलावा आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आने वाला है. लव लाइफ भी अच्छी जाएगी. बस अपने रूटीन को सही तरीके से फॉलो करते रहें और अपना ध्यान रखें. ■ **मकर**: काम में सफलता मिलेगी. दूसरों की बातों पर ध्यान ना दें. आने वाला समय सिर्फ आपका है. कल कोई नया मौका मिल सकता है. साथ ही पैसों की स्थिति भी पहले से बेहतर होने वाली है. इसके अलावा कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचें. खानपान का ध्यान रखें. जंक फूड से दूर रहने की

अदालतों पर भाजपा का नियंत्रण महाभियोग जरूरी है!

भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में देश की न्यायपालिका से परे लोगों का विश्वास उठ गया है. इसका कारण न्यायाधीशों की नियुक्ति में राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के प्रवक्ता और पदाधिकारी राज्यों के उच्च न्यायालयों में नियुक्त किए जा रहे हैं. दूसरा, सरकार की ओर से उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर दबाव है. इसके चलते खरा न्याय मिलना मुश्किल हो गया है. न्यायपालिका में २५ प्रतिशत न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाकर इन लोगों को पद से हटाया जाए, ये इस लायक हैं. विपक्ष तमिलनाडु-मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जी. आर. स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला रहा है. सौ से अधिक सांसदों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं. पाखंडी हिंदुत्ववादी अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस ने इस महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करनेवाले शिवसेना सांसदों के खिलाफ सत्यापन शुरू कर दिया है. न्यायमूर्ति स्वामीनाथन हिंदुत्ववादी हैं इसलिए भाजपा का कहना है कि उन पर महाभियोग चलाना गलत है. अदालत में जाति, धर्म और संप्रदाय को घसीटने का क्या कारण है? यहां धर्म या सेक्सुअल चार्ज कोई सवाल ही नहीं है. न्याय देवता का तराजू निष्पक्ष होता है, लेकिन भारतीय न्यायपालिका का तराजू फिलहाल भाजपा या संघ के हाथों में है और न्यायाधीश उनके इशारों पर काम कर रहे हैं. रोमनों की तरह, भारतीय न्याय देवता के भी कुछ प्रतीक थे. एक ऐसा सिंहासन जो आंथों में भी नहीं हिलता, एक ऐसा हृदय जो किसी भी भावना के आगे नहीं झुकता, बंधी आंखें जो किसी को भी पूर्वाग्रह या बुरी बुद्धि से नहीं देखतीं और सभी अपराधियों पर समान निश्चितता और निष्पक्ष शक्ति से गिरती तलवार. हालांकि, मोदी युग में न्यायदेवता के ये सभी प्रतीक नष्ट कर दिए गए हैं. अब न्यायपालिका को अपने हाथ में लेकर भारत में सांप्रदायिक और धार्मिक तनाव पैदा करना और उससे राजनीतिक लाभ उठाना संघ परिवार का यह ‘राष्ट्रीय कार्य’ जारी है.



